CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBHAG-3

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-3-79/X—909-79, dated January 19, 1983.

Notification

———

Miscellaneous

No. G-3-79/X—909-79

Dated Lucknow, January 19, 1983

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Regulations with a view to amending the Civil Service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh :

THE UTTAR PRADESH CIVIL SERVICE (TENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 1983

1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Civil Service (Tenth Amendment) Regulations, 1983. *Short title and commencement.*
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from October 28, 1980.

2. In the Uttar Pradesh Civil Service Regulations :— *Insertion of new Articles 351-AA and 919-A.*

(i) *After* the existing Article 351-A, the following new Article shall be *inserted*, namely :—

"351—AA In the case of a Government servant who retires on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings or an enquiry by Administrative Tribunal is pending on the date of retirement or is to be instituted after retirement, a provisional pension as provided in Article 919-A may be sanctioned." ; and

(ii) *After* Article 919, the following new Article shall be *inserted*, namely—

"919-A. (1) In cases referred to in Article 351—AA, the Head of Department shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service upto the date of retirement of the Government servant or if he was under suspension on the date of retirement, upto the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.

(2) The provisional pension shall be authorised for the period commencing from the date of retirement upto and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings or the enquiry by the Administrative Tribunal, as the case may be, final orders are passed by the competent authority.

(3) No death-*cum*-retirement gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings or the enquiry by the Administrative Tribunal and issue of final orders thereon.

(4) Payment of provisional pension made under clause (1) above, shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such Government servant upon conclusion of the proceedings or inquiry referred to in clause (3) but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period."

By order,
J. L. BAJAJ,
Vitta Sachiv.

NOTE—The hand-book captioned Civil Service Regulations (Parts I, IV and X) as adopted for application in Uttar Pradesh (First Edition) was published as corrected up to April 30, 1970. The following amendments were made subsequently :—

(1) Notification No. G—3—1932/X—915-73, dated November 1, 1973.
(2) Notification No. G—3—1732/X—914-73, dated November 13, 1973.
(3) Notification No. G—3—234/X—904(i)-62, dated October 7, 1974.
(4) Notification No. G—3—754/X—917-74, dated June 11, 1975.
(5) Notification No. G—3—3159/X—904(9)-60, dated October 6, 1975.
(6) Notification No. G—3—1476/X—52-74, dated June 5, 1976.
(7) Notification No. G—3—1928/X—908-70, dated October 8, 1976.
(8) Notification No. G—3—565/X—912(3)-74, dated April 20, 1977.
(9) Notification No. G—3—2133/X—904--78, dated December 29, 1980.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 59 सा० भाषा--23-2-83--(3719)--1983--10,000 (हि०)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–79/दस––909-79
लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (दसवां संशोधन) विनियमावली, 1983

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1––(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (दसवां संशोधन) विनियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

नया अनुच्छेद 351–क क और 919–क का बढ़ाया जाना।

2––उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में:—

(एक) वर्तमान अनुच्छेद 351–क के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"351–क क–ऐसे किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त होता है और जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक अधिकरण द्वारा कोई जांच लम्बित हो या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे संस्थित किया जाना हो तो अनुच्छेद 919–क में यथा उपबन्धित अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जा सकती है", और

(दो) अनुच्छेद 919 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"919–क (1) अनुच्छेद 351–क क में निर्दिष्ट मामलों में, *विभागाध्यक्ष ऐसी अधिकतम* पेंशन के बराबर अनन्तिम पेंशन दिये जाने को प्राधिकृत करेगा जो सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक तक या यदि वह सेवानिवृत्ति के दिनांक को निलम्बित हो तो उस दिनांक के, जब वह निलम्बित किया गया था, ठीक पूर्ववर्ती दिनांक तक अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुमन्य होता।

(2) अनन्तिम पेंशन सेवानिवृत्ति के दिनांक से उस दिनांक तक की अवधि के लिये जब, यथा-स्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जांच की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश दिया जाय, दिया जाना प्राधिकृत किया जायेगा।

(3) सरकारी सेवक को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जांच समाप्त न हो जाय और उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जाये।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1) के अधीन दिये गये अनन्तिम पेंशन के भुगतान का समायोजन खण्ड (3) में निर्दिष्ट कार्यवाही या जांच की समाप्ति के पश्चात् ऐसे सरकारी सेवक को स्वीकृत अन्तिम सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति किया जायगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनन्तिम पेंशन से कम हो या पेंशन स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कम कर दी जाय या रोक ली जाय तो कोई वसूली नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
जे० एल० बजाज,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

टिप्पणी:—उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग–1, 4 और 10) नामक हस्तपुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गई थी। बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये :—

(1) अधिसूचना संख्या–सा–3–1932/दस—915–73, दिनांक 1–11–1973
(2) अधिसूचना संख्या–सा–3–1732/दस—914–73, दिनांक 13–11–1973
(3) अधिसूचना संख्या–सा–3–234/दस—904 (1)-62, दिनांक 7–10–1974
(4) अधिसूचना संख्या सा–3–754/दस—917–74, दिनांक 11–6–1975
(5) अधिसूचना संख्या–सा–3–3159/दस—904(9)-60, दिनांक 6–10–75
(6) अधिसूचना संख्या–सा 3–1476/दस—52-74, दिनांक 5–6–1976
(7) अधिसूचना संख्या सा–3–1928/दस—908-70, दिनांक 8–10–1976
(8) अधिसूचना संख्या–सा–3–565/दस—912(3)-74, दिनांक 20–4–1977
(9) अधिसूचना संख्या–सा–3–2133/दस—904-78, दिनांक 29–12–1980

संख्या सा–3–79(1)/दस—909–79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
5—अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
भीष्म देव सिंह,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CSR (Civil Services Regulation) ~~Act~~)

Article – 370, 380

हिमाप्रपु०पी०-इ०पी०- 17 ला० प्रशासन-18-9-90-(2210)-40,00,000-(आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भीष्म देव सिंह,
संयुक्त सचिव ।

14300
400
14700
7350

1.1.96 से 10 माह
पूरा 10 माह का
औसत — वेशेष.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1431/दस–903-84

लखनऊ, दिनांक : 29 सितम्बर, 1984

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :––

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 1984

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 1984 कही जायगी।

(2) यह दिनांक 8 मई, 1984 से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 468 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में, स्तम्भ-1 में दिये गये अनुच्छेद 468 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्:––

स्तम्भ––1	स्तम्भ––2
468. The amount of pension that may be granted is determined by length of service as set-forth in Articles 474 to 485. Fractions of a year equal to six months and above shall be treated as a completed six monthly period for the purpose of calculating of any pension admissible under these Regulations.	468––पेंशन की धनराशि जो स्वीकृत की जाय, सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाती है। अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना करने में, किसी अर्द्ध वर्ष के भाग को जो तीन मास या इससे अधिक के बराबर हो, पूरा अर्द्ध वर्ष समझा जायेगा और उसे अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा।

आज्ञा से,

जे0 पी0 सिंह,

वित्त सचिव।

टिप्पणी:––उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग–1, 4 और 10) नामक हस्तपुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गई थी। बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये:––

(1) अधिसूचना संख्या सा–3–1932/दस–915/73, दिनांक 1 नवम्बर, 1973।
(2) अधिसूचना संख्या सा–3–1732/दस–914–73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973।
(3) अधिसूचना संख्या सा–3–234/दस–904(1)62, दिनांक 7 अक्तूबर, 1974।
(4) अधिसूचना संख्या सा–3–754/दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1975।
(5) अधिसूचना संख्या सा–3–3159/दस–904(9)60, दिनांक 6 अक्तूबर, 1975।
(6) अधिसूचना संख्या सा–3–1476/दस–52–74, दिनांक 5 जून, 1976।
(7) अधिसूचना संख्या सा–3––1928/दस–908–70, दिनांक 8 अक्तूबर, 1976।
(8) अधिसूचना संख्या सा–3–565/दस–912(3)–74, दिनांक 20 अप्रैल, 1977।
(9) अधिसूचना संख्या सा–3–2133/दस–904–78, दिनांक 29 दिसम्बर, 1980।
(10) अधिसूचना संख्या सा–3–79/दस–909–79, दिनांक 19 जनवरी, 1983।

संख्या सा–3–1431(1)/दस–903/84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

1––उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
2––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3––सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4––विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
5––अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. G-3-1431/X—903-84, dated September 29, 1984:

No. G-3—1431/X—903-84

Dated Lucknow, September 29, 1984

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Regulations with a view to amending the Civil Servic Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh :

THE UTTAR PRADESH CIVIL SERVICE (ELEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 1984

Short title and commencement.

1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Civil Service (Eleventh Amendment) Regulations, 1984.

(2) They shall come into force with effect from May 8, 1984.

Amendment of Article 468.

2. In the Civil Service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh, for Article 468 as given in column I, the Article as given in column II, shall be *substituted*:

COLUMN I	COLUMN II
468. The amount of pension that may be granted is determined by length of service as set-forth in Articles 474 to 485. Fractions of a year equal to six months and above shall be treated as a completed six monthly period for the purpose of calculating of any pension admissible under these Regulations.	468. The amount of pension that may be granted is determined by length of service. In calculating the length of qualifying service, fractions of a half year equal to three months and above shall be treated as a completed one-half year and reckoned as qualifying service.

By order,

J. P. SINGH,
Vitta Sachiv.

NOTE—The hand book captioned Civil Service Regulations (Parts I, IV and X) as adopted for application in Uttar Pradesh (First Edition) was published as corrected upto April 30, 1970. The following Amendments were made subsequently :

(1) Notification no. G-3-1932/X—915-73, dated November 1, 1973.
(2) Notiification no. G-3-1732/X—914-73, dated November 13, 1973.
(3) Notification no. G-3-234/X—904(1)-62, dated October 7, 1974.
(4) Notification no. G-3-754/X—917-74, dated June 11, 1975.
(5) Notification no. G-3-3159/X—904(9)-60, dated October 6, 1975.
(6) Notification no. G-3-1476/X—52-74, dated June 5, 1976.
(7) Notification no. G-3-1928/X—908-70, dated October 8, 1976.
(8) Notification no. G-3,565/X—912 (3)-74, dated April 20, 1977.
(9) Notification no. G-3-2133/X—904-78, dated December 29, 1980.
(10) Notification no. G-3-79/X—909-79, dated January 19, 1983.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 20 सा० भाषा–18–10–84–(2302)–1984–10,000 (मेक०)।

CC-0. Panjab Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (पेंशन-1) अनुभाग-3
सं0 सा-3-424/दस-93(1)/89
लखनऊ दिनांक 12 जुलाई 1996

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टिसे निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवां संशोधन) विनियमावली-96

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवां संशोधन) विनियमावली 1996 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 470 का निकाला जाना

2- उत्तर प्रदेश से उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में नीचे विनिर्दिष्ट अनुच्छेद 470 निकाल दिया जायेगा।

वर्तमान अनुच्छेद

470 (a) The full pension admissible under the rules is not to be given as a matter of course, or unless the service rendered has been really approved.

(b) If the service has not been thoroughly satisfactory the authority sanctioning the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper.

Provided that in cases where the authority sanctioning pension is other than the appointing authority, no order regarding reduction in the amount of pension shall be made without the approval of the appointing authority.

Note :- For the purpose of this Article 'appointing authority' shall mean the authority which is competent to make substantive appointment to the post or service from which the officer concerned retires.

आज्ञा से,
(पी. के. मिश्रा)
सचिव

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

टिप्पणी :- उत्तर प्रदेश में व्रवृत्त होने के लिए यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग-I, 4 और 10) नामक हस्तपुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गई थी । बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये :-

(1) अधिसूचना संख्या सा-3-1932/दस-915-73, दिनांक 1-11-1973 ✓
(2) अधिसूचना संख्या सा-3-1732/दस-914-73, दिनांक 13-11-1973 ✓
(3) अधिसूचना संख्या सा-3-234/दस-904(1)-62, दिनांक 7-10-1974 ✓
(4) अधिसूचना संख्या सा-3-754/दस-917-74, दिनांक 11-6-1975, ✓
(5) अधिसूचना संख्या सा-3-3159/दस-904(9)-60, दिनांक 6-10-1975 ✓
(6) अधिसूचना संख्या सा-3-1476/दस-52-74, दिनांक 5-6-1976
(7) अधिसूचना संख्या सा-3-1928/दस-908-70, दिनांक 8-10-1976
(8) अधिसूचना संख्या सा-3-565/दस-912(3)-74, दिनांक 20-4-1977
(9) अधिसूचना संख्या सा-3-2133/दस-904-78, दिनांक 29-12-1980 ✓
(10) अधिसूचना संख्या सा-3-79/दस-909-79, दिनांक 19-1-1983 ✓
(11) अधिसूचना संख्या सा-3-1431/दस-903-84 दिनांक 29-9-1984 ✓

(II)/

संख्या सा-3-424/दस-233/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) राज्यपाल के सचिव ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) सचिव, विधान सभा सचिवालय ।
(4) सचिव, विधान परिषद सचिवालय ।
(5) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।
(6) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
(7) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इंदिराभवन, लखनऊ ।
(8) समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
(9) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित गजट में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से,

संयुक्त सचिव

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBHAG - 3.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-3-424/X-933/89, Dated February 12, 1996.

Notifications
Miscellaneous

No. G-3-424/X-933/89,
Dated Lucknow February 12, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Regulations with a view to amending the Civil Service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh:

THE UTTAR PRADESH CIVIL SERVICE (TWELFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 1996.

Short title and commencement. 1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Civil Service (Twelfth - Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force atonce.

Omission of Article 470 2. In the civil service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh Article 470 specified below shall be omitted:

470 (a) The full pension admissible under the rules is not to be given as a matter of course, or unless the service rendered has been really approved.

(b) If the service has not been thoroughly satisfactory the authority sanctioning the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper.

Provided that in cases where the authority sanctioning pension is other than the appointing authority, no order regarding reduction in the amount of pension shall be made without the approval of the appointing authority.

...

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या:5231।/जेड/6-96, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. निदेशक/ सचिव, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ ।
4. मंत्री, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ ।
5. गुप्त सम्बन्ध अनुभाग-2, 3 एवं 4 ।

आज्ञा से,

(सन्तोष चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Note - For the purpose of this Article 'appointing authority' shall mean the authority which is competent to make substantive appointment to the post or service from which the officer concerned retires.

By order,

(P.K. Misra)
Sachiv.

Note:- The hand-book captioned Civil Service Regulations (Part I, IV and X) as adopted for application in Uttar Pradesh (First Edition) was published as corrected upto April 30, 1970. The following amendments were made subsequently:-

(1) Notification No. G-3-1932/X-915-73, dated November, 1973.
(2) Notification No. G-3-1732/X-914-73, dated November 13,1973.
(3) Notification No. G-3-234/X-904(i)-62, Dated October 7,1974.
(4) Notification No. G-3-754/X-917-74, dated June 11, 1975.
(5) Notification No. G-3-3159/X-904(9)-60, dated October 6,1975.
(6) Notification No.G-3-1476/X-52-74, dated June 5, 1976.
(7) Notification No.G-3-1928/X-908-70, dated October 8, 1976.
(8) Notification No.G-3-565/X-912(3)-74, dated April 20, 1977.
(9) Notification No. G-3-2133/X-904-78, dated December 29,1980.
(10) Notification No.G-3-79/X-909-79, dated January 19, 1983.
(11) Notification No. G-3-1431/X-903-84. dated September 29,1984.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh